



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022025-261143
CG-DL-E-18022025-261143

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 859]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2025/माघ 29, 1946

No. 859]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2025/MAGHA 29, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2025

का.आ. 865(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा किया जाना अपेक्षित है कि बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में दी जाने वाली सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 32 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाए;

और, केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 3493(अ), तारीख 16 अगस्त, 2024 द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 अगस्त, 2024 से छह मास की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

और, उक्त उप-खण्ड (vi) के परन्तुक में यह उपबंध है कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में लोक उपयोगिता सेवा की घोषणा का विस्तार अपेक्षित है, तो इसे छह मास से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ठ) के उपखंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसकी यह राय है कि सार्वजनिक हित में विस्तार अपेक्षित है, अधिसूचना संख्या का. आ. 3493(अ), तारीख 16 अगस्त, 2024 में निर्दिष्ट अवधि को 19 फरवरी, 2025 से छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाती है, जिसके दौरान उक्त औद्योगिक उपक्रमों में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा. सं. एस-11017/04/2024-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2025

S.O. 865(E).—WHEREAS, the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services in the Bank Note Paper Mill India Private Limited, Mysore, Karnataka, which is covered under item 32 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND, WHEREAS, the Central Government has declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th August, 2024, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 3493(E), dated the 16th August, 2024;

AND, WHEREAS, the proviso to said sub-clause (vi) provides that if the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the declaration of public utility service, it may be extended for a period not exceeding six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government being of the opinion that in the public interest requires extension, hereby extends the period specified in the notification number S.O.3493(E), dated the 16th August, 2024 for a further period of six months from the 19th February, 2025 during which the services engaged in the said industries to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F. No. S-11017/04/2024 -IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.